बुधवार, 11 मार्च, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08



कीर्ति आजाद का बयान विवाद

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

अक्षय की O.M.G. 3 में नहीं होगी रानी

Page-05



कैबिनेट के बड़े फैसले

जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ा,

कनेक्टिविटी परियोजनाओं को मंजूरी

राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के आर्थिक ढांचे, आधारभूत संरचना और जनकल्याण से जुड़ी कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट है कि केवल नई परियोजनाओं की घोषणा ही नहीं की जा रही, बल्कि उन्हें विकसित भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ जोड़ते हुए क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने का लिया गया। इसके लिए करीब 8.69 लाख करोड़ रुपये का बड़ा प्रावधान किया गया है। इस योजना का लक्ष्य अब सिर्फ पाइपलाइन बिछाना नहीं, बल्कि हर गांव में टिकाऊ और भरोसेमंद जल आपूर्ति व्यवस्था स्थापित करना है। इसके तहत 'सुजल भारत' नाम से एक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा भी तैयार किया जाएगा, जिससे जल स्रोत से लेकर





घरों तक की पूरी व्यवस्था को डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा।सरकार के अनुसार, वर्ष 2019 में देश के केवल 17 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक ही नल का जल पहुंचता था, जो अब बढ़कर 81 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इस विस्तार से ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव आया है। कई अध्ययनों में सामने आया है कि लाखों महिलाएं रोजाना पानी लाने की कठिन मेहनत से मुक्त हुई हैं और अब वे शिक्षा, रोजगार तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में भाग ले पा रही हैं। स्वच्छ जल की उपलब्धता से जलजनित बीमारियों में भी कमी देखी गई है। कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े परिवहन प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में उज्जैन को दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले बदनावर–पेटलावद–थांदला–तिमरवानी मार्ग को चार लेन में विकसित किया जाएगा। लगभग 80 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से यात्रा का समय कम होगा और माल परिवहन सस्ता बनेगा। इससे धार और झाबुआ जैसे आदिवासी बहुल जिलों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए करीब 31 किलोमीटर लंबा हरित क्षेत्रीय संपर्क मार्ग बनाने को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर एयरपोर्ट तक तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार, पर्यटन और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है।



ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग

राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

विधानसभा चुनाव 2026 से पहले पश्चिम बंगाल एक अखाड़े में तब्दील हो गया है, जहां पिछले 15 सालों से सरकार चला रही तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हर दिन चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं. इन दिनों चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर हैं. खासकर पिछले 24 घंटे के दौरान ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से लेकर चंद्रिमा भट्टाचार्य और अन्य टीएमसी नेताओं ने सीईसी पर कई गंभीर आरोप लगाये. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल के अफसरों को धमकी दी. ममता बनर्जी ने सोमवार को धर्मतला के मेट्रो चैनल पर धरनास्थल से कहा कि आयोग का यह दुस्साहस है, जिसे स्वीकार नहीं किया जायेगा. चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि आयोग का उद्देश्य केवल कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना है. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. वोटर लिस्ट और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाना राजनीतिक हथियार है.

यूपी में कैब एग्रीगेटर कंपनियों के लिए नई व्यवस्था

पंजीकरण और लाइसेंस अनिवार्य

राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में संचालित होने वाली कैब एग्रीगेटर कंपनियों के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब ओला और उबर जैसी सभी टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों को संचालन शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करना होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और परिवहन सेवाओं को अधिक व्यवस्थित बनाना है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि यह व्यवस्था केंद्र सरकार के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 में किए गए संशोधनों के अनुरूप लागू की जा रही है। एक जुलाई 2025 को केंद्र ने टैक्सी एग्रीगेटर कंपनियों के लिए नए नियम तय किए थे, जिन्हें अब राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत कैब चलाने वाले सभी चालकों को चिकित्सकीय परीक्षण और पुलिस सत्यापन से गुजरना होगा, जबकि वाहनों की फिटनेस जांच भी



अनिवार्य होगी। सरकार ने एग्रीगेटर कंपनियों के लिए लाइसेंस शुल्क भी तय किया है, जिसके तहत लाइसेंस के लिए पांच लाख रुपये जमा करने होंगे और आवेदन शुल्क 25 हजार रुपये होगा। यह लाइसेंस पांच वर्ष के लिए मान्य रहेगा तथा नवीनीकरण के लिए पांच हजार रुपये शुल्क देना होगा। इसके अलावा सरकार एक विशेष ऐप भी विकसित करेगी, जिसमें कैब सेवाओं से जुड़ी जानकारी, ड्राइवरों का विवरण और अन्य आवश्यक सूचनाएं आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा

राहुल भाटिया को सौंपी अंतरिम जिम्मेदारी

राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड द्वारा संचालित इंडिगो ने मंगलवार को घोषणा की कि उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला दिसंबर में एयरलाइन के इतिहास के सबसे बड़े उड़ान संकट के बाद सामने आया है।कंपनी ने बताया कि एयरलाइन के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया फिलहाल अंतरिम आधार पर कंपनी का प्रबंधन संभालेंगे।अपने इस्तीफे के पत्र में पीटर एल्बर्स ने राहुल भाटिया को संबोधित करते हुए लिखा कि आपसे हुई बातचीत के अनुसार, व्यक्तिगत कारणों से मैं आज से इंडिगो के सीईओ पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उनकी नोटिस अवधि को माफ कर दिया जाए। लेकिन अपनी सफलताओं के बावजूद, एल्बर्स का कार्यकाल दिसंबर 2025 में एक बड़े परिचालन संकट से दागदार हो गया। यह उड़ान संकट इंडिगो द्वारा पायलटों की थकान को रोकने के लिए बनाए गए नए नियमों को लागू करने में हुई



विफलता के कारण उत्पन्न हुआ। 3 से 5 दिसंबर के बीच, इंडिगो ने 2,500 से अधिक उड़ानें रद्द कीं और लगभग 1,900 उड़ानों में देरी की, जिससे 3 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए। डीजीसीए ने एल्बर्स पर 22.20 करोड़ का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया और उन्हें सीधे कारण बताओ नोटिस जारी किए। हालांकि शुरुआत में उनके इस्तीफे की मांग का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इस संकट ने एयरलाइन की समयबद्धता की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचाया।

समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी कहा–

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समय आ गया है, संसद करे फैसला

राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के विचार पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में अलग-अलग समुदायों के पर्सनल लॉ से पैदा होने वाली जटिलताओं को एक समान नागरिक कानून के माध्यम से काफी हद तक दूर किया जा सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान की।सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने कहा कि न्यायपालिका सीधे तौर पर ऐसे कानूनों को शून्य घोषित नहीं कर सकती, जब तक उनकी जगह कोई व्यापक वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद न हो। उनका कहना था कि यदि पर्सनल लॉ को अचानक निरस्त कर दिया गया तो कानूनी शून्यता की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए इस विषय पर अंतिम निर्णय लेना विधायिका का अधिकार है और संसद को इस दिशा में व्यापक कानून बनाने पर विचार करना चाहिए।न्यायमूर्ति बागची ने यह भी कहा कि पर्सनल लॉ से जुड़ी कई प्रथाओं को अदालत द्वारा सीधे अमान्य घोषित करना व्यावहारिक रूप से कठिन हो सकता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम पुरुष एकतरफा तलाक देने की विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाता है, ऐसे में क्या पर्सनल लॉ के तहत हुए सभी बहुविवाह संबंधों को अचानक अमान्य घोषित किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के बड़े बदलाव के लिए विधायी प्रक्रिया आवश्यक है।यह मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) अनुप्रयोग अधिनियम, 1937 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह कानून उत्तराधिकार जैसे मामलों में मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करता है।याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि शरिया आधारित उत्तराधिकार नियमों के तहत महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल आधा हिस्सा मिलता है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि 1937 के कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाता है तो उसकी जगह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 लागू किया जा सकता है, जिसमें पुरुष और महिला



दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। हालांकि न्यायमूर्ति बागची ने इस तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 372 के अनुसार पहले से लागू कानून तब तक प्रभावी रहते हैं, जब तक उन्हें विधायिका द्वारा बदला न जाए।सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी सावधानी बरतने की बात कही कि सुधार की प्रक्रिया में कहीं ऐसा न हो कि मुस्लिम महिलाओं को पहले से मिले अधिकार भी प्रभावित हो जाएं। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका में संशोधन करने का सुझाव भी दिया।गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के रूप में किया गया है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करने की बात कही गई है। हालांकि यह प्रावधान



न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। फिलहाल भारत में गोवा और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू है, जबकि देशभर में इस विषय पर लंबे समय से बहस जारी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'रक्षा बल विजन 2047' जारी किया

आधुनिक और आत्मनिर्भर सेना का रोडमैप पेश

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 'रक्षा बल विजन 2047' दस्तावेज़ जारी किया। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक, एकीकृत और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। इसमें आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, उन्नत तकनीक और तीनों सेनाओं के बेहतर समन्वय के माध्यम से 2047 तक विश्वस्तरीय सेना बनाने का लक्ष्य रखा गया है।



टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित साउथ ब्लॉक में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान 'रक्षा बल विजन 2047: भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना का रोडमैप' नामक दस्तावेज़ जारी किया। यह व्यापक विजन दस्तावेज़ एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय द्वारा तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को एक आधुनिक, एकीकृत और तकनीकी रूप से उन्नत सैन्य शक्ति में परिवर्तित करना है, ताकि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में रक्षा क्षेत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।जारी किए गए इस विजन दस्तावेज़ में तीनों सेनाओं—थल सेना, नौसेना और वायु सेना—के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। दस्तावेज़ में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए सैन्य बलों के बीच तालमेल और सामूहिक रणनीति अत्यंत आवश्यक है। इससे सैन्य योजना, अभियान संचालन और संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सकेगा।विजन दस्तावेज़ में भविष्य के युद्धों की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रशिक्षण प्रणाली को भी विशेष महत्व दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान समय में युद्ध के स्वरूप तेजी से बदल रहे हैं और साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारतीय सशस्त्र बलों को इन तकनीकों से लैस करना समय की आवश्यकता है। इसके साथ ही दस्तावेज़ में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर भी विशेष बल दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि देश की रक्षा आवश्यकताओं को अधिक से अधिक स्वदेशी तकनीकों और उपकरणों के माध्यम से पूरा किया जाए। इसके लिए घरेलू रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन देने, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी मजबूत करने की योजना बनाई गई है। इससे न केवल देश की रक्षा क्षमता मजबूत होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। 'रक्षा बल विजन 2047' दस्तावेज़ में अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित रोडमैप तैयार किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं के विकास, संस्थागत सुधारों और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने का उल्लेख किया गया है। इस रोडमैप के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों को विश्वस्तरीय सैन्य शक्ति के रूप में विकसित करने की दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा।कार्यक्रम के दौरान देश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा भविष्य की रणनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा, राहुल भाटिया ने संभाली अंतरिम जिम्मेदारी

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को संचालित करने वाली इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने मंगलवार को घोषणा की कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला दिसंबर 2025 में एयरलाइन के अब तक के सबसे बड़े उड़ान संकट के बाद सामने आया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने फिलहाल अंतरिम आधार पर एयरलाइन के संचालन की जिम्मेदारी संभाल ली है। पीटर एल्बर्स ने अपने इस्तीफे के पत्र में सह-संस्थापक राहुल भाटिया को संबोधित करते हुए लिखा कि हमारी बातचीत के अनुसार मैं व्यक्तिगत कारणों से आज से इंडिगो के सीईओ पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने अनुरोध किया कि उनकी नोटिस अवधि को माफ कर दिया जाए। एल्बर्स ने कहा कि सितंबर 2022 से इंडिगो के सीईओ के रूप में सेवा करना उनके लिए सम्मान और सौभाग्य की बात रही है। उन्होंने कहा कि इंडिगो परिवार का हिस्सा बनना और कंपनी की विकास यात्रा में योगदान देना उनके लिए बेहद खुशी का विषय रहा। उनके कार्यकाल के दौरान एयरलाइन ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। सितंबर 2022 में पद संभालने के बाद तीन साल से कुछ अधिक समय में ही इंडिगो ने 10 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व हासिल किया। यह संकट एयरलाइन द्वारा पायलटों की थकान को कम करने के लिए बनाए गए नए नियमों को लागू करने में विफलता के कारण पैदा हुआ था। 3 से 5 दिसंबर के बीच इंडिगो को 2,500 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि करीब 1,900 उड़ानें देरी से संचालित हुईं। इस स्थिति से तीन लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एल्बर्स पर 22.20 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। हालांकि शुरुआत में उनके इस्तीफे की मांग का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इस संकट ने एयरलाइन की समयबद्धता और विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचाया।



मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

जल जीवन मिशन 2028 तक जारी, ₹8.69 लाख करोड़ की स्वीकृति

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ने गैस आपूर्ति नियंत्रित करने के लिए उठाए सख्त कदम

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिका द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर किए गए हमले के बाद तेज हुए युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य में पैदा हुई बाधा के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर संकट गहराने लगा है। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने मार्च 2026 से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू करते हुए देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति तथा वितरण को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं और आवश्यक क्षेत्रों के लिए गैस की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार देश की सभी तेल रिफाइनरी कंपनियों को उपलब्ध प्रोपेन और ब्यूटेन से अधिकतम मात्रा में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उत्पादन करने का आदेश दिया गया है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि इन गैसों का उपयोग पेट्रो-रसायन या अन्य औद्योगिक उत्पादों के लिए नहीं किया जाएगा। इन संसाधनों का उपयोग मुख्य रूप से घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति के लिए किया जाएगा।सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 5 का उपयोग करते हुए तेल विपणन कंपनियों के लिए आपूर्ति से संबंधित सीमाएं भी तय कर दी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां—भारतीय तेल निगम, हिन्दुस्तान



पेट्रोलियम निगम और भारत पेट्रोलियम निगम—को निर्देश दिया गया है कि खरीदी गई तरलीकृत पेट्रोलियम गैस को प्राथमिकता के आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। जमाखोरी रोकने के लिए गैस सिलेंडर की नई बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतराल अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने प्राकृतिक गैस के वितरण को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश 2026 लागू किया है। इसके तहत घरेलू पाइप गैस, कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस और उर्वरक कारखानों को गैस आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि कृषि और परिवहन क्षेत्र प्रभावित न हों। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में आई बाधा के कारण भारत को मिलने वाली तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है।

पाकिस्तान में पेट्रोल संकट गहराया कीमतों में 55 रुपये की बढ़ोतरी

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पश्चिम एशिया में ईरान से जुड़े तनाव और अमेरिका-इजराइल के साथ जारी संघर्ष के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत पैदा हो गई है। रमजान के पवित्र महीने के दौरान देश में ईंधन संकट ने आम लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर तेल आपूर्ति पर पड़ा है, जिसके कारण पाकिस्तान में कई जगह पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी देखने को मिल रही है। स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तत्काल प्रभाव से 55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत लगभग 335.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत करीब 321.70 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। कीमतों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी से देश में हाहाकार की स्थिति बन गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बढ़ती तेल कीमतों और ईंधन की कमी को देखते हुए कई सख्त कदमों का ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि सरकारी कार्यालय अब सप्ताह में केवल चार दिन ही खुलेंगे और आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। ईंधन की बचत के लिए सप्ताह में एक अतिरिक्त अवकाश भी दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इस सप्ताह के अंत से देशभर के स्कूल दो सप्ताह के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहीं उच्च शिक्षा संस्थानों में तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इन प्रतिबंधों का असर बैंकों पर नहीं पड़ेगा और बैंक सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। सरकार ने ईंधन की बचत के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर भी नियंत्रण लगाने का फैसला किया है। अगले दो महीनों तक सरकारी वाहनों को 50 प्रतिशत कम ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी सीमित रखी जाएगी, ताकि ईंधन की खपत को कम किया जा सके। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर ईंधन समाप्त होने की स्थिति बन गई है। कई पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जबकि कुछ पंपों पर इतना ही पेट्रोल बचा है कि वे केवल एक से डेढ़ घंटे तक ही काम कर पा रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि पिछले दो से तीन दिनों से नई आपूर्ति नहीं पहुंची है, जिससे संकट और गहरा गया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले करों और लेवी में बदलाव करते हुए कीमतों में यह बढ़ोतरी की है।





संपादक की कलम से

सूचना तक पहुंच पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गई है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग कुछ ही सेकंड में देश-दुनिया की खबरें जान सकते हैं। लेकिन इसी तेजी के साथ एक गंभीर समस्या भी सामने आई है—फेक न्यूज यानी भ्रामक और झूठी खबरों का तेजी से प्रसार। आज यह समस्या केवल मीडिया की विश्वसनीयता ही नहीं, बल्कि समाज की शांति और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आम नागरिक को अपनी बात रखने का मंच दिया है। यह लोकतंत्र के लिए सकारात्मक पहलू है, लेकिन जब बिना सत्यापन के सूचनाएं साझा की जाती हैं तो वे अफवाह का रूप ले लेती हैं। कई बार अधूरी या झूठी जानकारी लोगों की भावनाओं को भड़काती है और समाज में तनाव पैदा कर देती है। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों ने विवाद और हिंसा तक को जन्म दिया।फेक न्यूज का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह धीरे-धीरे लोगों के बीच भ्रम और अविश्वास का माहौल पैदा करती है। जब लगातार झूठी खबरें फैलती हैं तो आम नागरिक के लिए सही और गलत जानकारी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इससे मीडिया संस्थानों की साख भी प्रभावित होती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा कमजोर पड़ने लगता है।इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार, मीडिया संस्थानों और समाज तीनों की साझा जिम्मेदारी बनती है। सरकार को ऐसे नियम और तंत्र विकसित करने चाहिए जो गलत सूचनाओं के प्रसार पर प्रभावी रोक लगा सकें। वहीं मीडिया संस्थानों को तथ्य आधारित और जिम्मेदार पत्रकारिता को और मजबूत करना होगा।सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आम नागरिक की है। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि किसी भी खबर को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना आवश्यक है। जागरूक नागरिक ही फेक न्यूज के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।डिजिटल युग में सूचना की शक्ति बहुत बड़ी है। यदि इसका उपयोग जिम्मेदारी और विवेक के साथ किया जाए तो यह समाज को जागरूक और सशक्त बना सकती है। लेकिन यदि झूठी और भ्रामक सूचनाओं को बिना जांचे-परखे फैलाया जाए तो यह समाज में भ्रम और अशांति का कारण भी बन सकती है। इसलिए आज समय की मांग है कि हम सभी मिलकर सच और जिम्मेदार सूचना संस्कृति को बढ़ावा दें।

संसद के बाहर विपक्ष का हंगामा

पश्चिम एशिया मुद्दे पर सरकार को घेरा

संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने पश्चिम एशिया संकट को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर इस मुद्दे पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि संकट से देश की अर्थव्यवस्था और तेल कीमतों पर असर पड़ सकता है।



टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने संसद के प्रवेश द्वार मकर द्वार की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से निपटने के सरकार के तरीके के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों के हाथों में पोस्टर और बैनर भी दिखाई दिए, जिनके माध्यम से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए।प्रदर्शन के दौरान एक बैनर भी दिखाया गया, जिस पर लिखा था "प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं।" इस बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ लगी हुई थीं। विपक्षी सांसदों का आरोप था कि सरकार पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने से बच रही है।इस विरोध प्रदर्शन में वे सांसद भी शामिल थे जिन्हें बजट सत्र के पहले चरण के दौरान अव्यवस्थित व्यवहार के कारण लोकसभा से सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया था। विपक्षी सांसदों ने सरकार की विदेश नीति और पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। सांसदों का कहना था कि इतने गंभीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार को संसद के माध्यम से देश के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस बीच, दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सांसद संध्या राय ने सत्र की अध्यक्षता की, जबकि राज्यसभा में सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने कार्यवाही का संचालन किया। सदन की कार्यवाही के दौरान भी विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और तख्तियां दिखाते हुए नारेबाजी करने लगे, जिससे कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही प्रभावित भी हुई।इससे एक दिन पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद में इस गंभीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा कराने से बच रही है।रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा से इसलिए बच रही है क्योंकि इससे यह उजागर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और इजरायल के साथ किस तरह के समझौते कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष भारत की जनता पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट से देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यदि वहां की स्थिति और गंभीर होती है तो इसका प्रभाव शेयर बाजार और आर्थिक व्यवस्था पर भी दिखाई देगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है तो सरकार संसद में इस पर चर्चा करने से क्यों बच रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पश्चिम एशिया के मुद्दे पर संसद में चर्चा चाहता है और इसके बाद अन्य विषयों पर भी चर्चा की जा सकती है। उनके अनुसार ईंधन की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी और आर्थिक प्रभाव जैसे मुद्दे सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े हैं, इसलिए इन पर संसद में गंभीर चर्चा होना जरूरी है। विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि ऐसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में खुली बहस लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है और इससे देश की विदेश नीति को लेकर स्पष्टता भी सामने आती है।

ट्रॉफी मंदिर पहुंची तो भड़के कीर्ति आजाद, बोले—खेल को धर्म से मत जोड़ो

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय



तृणमूल कांग्रेस के सांसद और 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य कीर्ति आजाद ने भारतीय टीम द्वारा टी20 विश्व कप जीत के बाद ट्रॉफी को मंदिर ले जाने के कदम की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव, मुख्य कोच गौतम गंभीर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह पर सवाल उठाते हुए कहा कि खेल और खिलाड़ी किसी धर्म या जाति से जुड़े नहीं होते। भारतीय टीम घरेलू मैदान पर टी20 विश्व कप का खिताब बचाने वाली पहली टीम भी बन गई। इस ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव, मुख्य कोच गौतम गंभीर और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह स्टेडियम के पास स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां ट्रॉफी के साथ भगवान का आशीर्वाद लिया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कीर्ति आजाद ने कहा कि टीम इंडिया विभिन्न धर्मों और समुदायों के खिलाड़ियों से बनी है और उसकी जीत पूरे देश की जीत होती है। उन्होंने कहा कि जब भारतीय टीम ने जीत हासिल की तो 140 करोड़ भारतीयों को गर्व और खुशी महसूस हुई। एक खिलाड़ी के रूप में उनका मानना है कि खेल को धर्म से जोड़ना उचित नहीं है और खिलाड़ियों की पहचान केवल खेल से होनी चाहिए।कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि 1983 में जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता था, तब टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के खिलाड़ी थे और उस समय ट्रॉफी को पूरे देश के गौरव के रूप में देखा गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ट्रॉफी को मंदिर ले जाया जा सकता है तो फिर मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में क्यों नहीं ले जाया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, किसी एक व्यक्ति या परिवार का नहीं। उनके अनुसार यह ट्रॉफी हर भारतीय की है और इसे किसी एक धर्म की जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

एलपीजी की कमी पर विपक्ष का हमला

सरकार पर झूठ बोलने का आरोप

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

गैस सिलेंडरों की कथित कमी और गैस कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मंगलवार को सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार केवल बड़े-बड़े दावे करती है, जबकि आम लोगों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, हाल ही में वैश्विक स्तर पर उत्पन्न भू-राजनीतिक तनाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण ईंधन आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ गया है। इसी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, आपूर्ति और समान वितरण को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। इस कानून के तहत सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को नियंत्रित कर सकती है ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद के प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष को बताया गया था कि देश में गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों पर बोझ नहीं डालने की बात करती है, लेकिन एक सप्ताह के भीतर ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गईं। उनके अनुसार सरकार के फैसलों का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन सरकार ने इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी। तिवारी ने कहा कि पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध भारत की ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें बढ़ा दी हैं और बेंगलुरु, मुंबई सहित कई शहरों में रसोई गैस की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। उनका कहना था कि यदि यह युद्ध लंबे समय तक चलता है, तो इसका असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर और अधिक पड़ सकता है।

गिरीश मातृभूतम की सफलता का सफर

कैसे फ्रेशवर्क्स बनी हजारों करोड़ की कंपनी

फ्रेशवर्क्स के संस्थापक गिरीश मातृभूतम की कहानी संघर्ष और सफलता का प्रेरक उदाहरण है। बारहवीं कक्षा में असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आगे चलकर एक वैश्विक टेक कंपनी खड़ी की। एक साधारण ग्राहक सेवा समस्या से प्रेरित होकर उन्होंने फ्रेशवर्क्स की शुरुआत की। आज उनकी कंपनी दुनिया भर में काम कर रही है कई बार जीवन की छोटी-सी समस्या भी बड़ा अवसर बन जाती है। फ्रेशवर्क्स के संस्थापक और सीईओ गिरीश मातृभूतम की कहानी इसी का उदाहरण है। एक साधारण ग्राहक सेवा की समस्या से उन्हें ऐसा विचार मिला जिसने आगे चलकर एक वैश्विक कंपनी का रूप ले लिया। आज उनकी कंपनी हजारों करोड़ रुपये की बन चुकी है और दुनिया भर की कंपनियों को कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा रही है। गिरीश मातृभूतम की सफलता की शुरुआत एक साधारण घटना से हुई। अमेरिका से भारत लौटने के बाद उन्होंने एक नया टेलीविजन खरीदा, लेकिन कुछ ही दिनों में वह खराब हो गया। उन्होंने कंपनी के सर्विस सेंटर से कई बार संपर्क किया, ईमेल और कॉल किए, लेकिन उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। जब उन्होंने अपनी परेशानी सोशल मीडिया पर लिखी तो कंपनी तुरंत सक्रिय हो गई। इस घटना से गिरीश को एहसास हुआ कि दुनिया को बेहतर कस्टमर सर्विस सिस्टम की जरूरत हैगिरीश का जन्म तमिलनाडु के त्रिची शहर में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता एक सरकारी बैंक में काम करते थे। बचपन में ही उनके माता-पिता अलग हो गए, जिससे परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई में वे औसत छात्र थे और बारहवीं की बोर्ड



परीक्षा में असफल भी हो गए। इस असफलता के कारण उन्हें लोगों की आलोचनाएं भी सुननी पड़ीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बारहवीं में असफल होने के बाद गिरीश ने दोबारा पढ़ाई की और अपनी शिक्षा पूरी की। बाद में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चेन्नई चले गए। वे किताबों से ज्यादा अनुभव से सीखने में विश्वास रखते थे। इसी दौरान उन्होंने तकनीक और सॉफ्टवेयर की दुनिया को समझना शुरू किया। उनकी यही सीख आगे चलकर उनके करियर में बेहद काम आई। इंजीनियरिंग के बाद गिरीश एमबीए करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उनके पिता ने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर उनकी पढ़ाई का इंतजाम किया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने छोटे-मोटे काम किए और जावा भाषा सीखकर दूसरों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्होंने जावा प्रशिक्षण का एक संस्थान भी खोला, लेकिन वह ज्यादा समय तक नहीं चला। बाद में वे अमेरिका गए और एचसीएल में काम किया, जहां उन्होंने कंपनियों की कार्यप्रणाली और कस्टमर सर्विस सिस्टम को करीब से समझा। वर्ष 2010 में गिरीश ने अपने मित्र शान कृष्णासामी के साथ चेन्नई में फ्रेशवर्क्स की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य आसान और किफायती कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर तैयार करना था। शुरुआत में निवेशकों को मनाना आसान नहीं था, लेकिन लगातार प्रयास के बाद 2011 में एक्सेल ने कंपनी में लगभग 10 लाख डॉलर का निवेश किया। इसके बाद कंपनी तेजी से आगे बढ़ी और दुनिया भर की कंपनियों को क्लाउड-आधारित कस्टमर सर्विस समाधान देने लगी। फ्रेशवर्क्स की सफलता ने भारतीय स्टार्टअप दुनिया में एक नया उदाहरण पेश किया। वर्ष 2021 में कंपनी अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। उस समय कंपनी के लगभग 500 कर्मचारी करोड़पति बन गए। आज फ्रेशवर्क्स के कार्यालय भारत, अमेरिका, पेरिस और नीदरलैंड समेत कई देशों में हैं। कंपनी की ग्राहक सूची में होंडा, सिस्को और तोशिबा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। वर्ष 2025 तक कंपनी की संपत्ति करीब 7800 करोड़ रुपये बताई जाती है।
।

इस दिन जारी होंगे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के एडमिट कार्ड



उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति जल्द ही UP Police Sub Inspector (SI) भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को समय रहते इसे डाउनलोड कर सकते हैं. UP Police SI Admit Card 2026 में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिन्हें उम्मीदवारों को ध्यान से चेक करना होगा. एडमिट कार्ड में उम्मीदवार से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी, परीक्षा से जुड़ी जानकारी और जरूरी निर्देश शामिल होते हैं. एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, परीक्षा का समय, शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम और गेट बंद होने का समय जैसी जानकारी दी होगी. इसके अलावा उम्मीदवार की कैटेगरी, परीक्षा केंद्र से जुड़े निर्देश और परीक्षा के दौरान पालन करने वाले नियम भी लिखे होंगे. यदि एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की गलती है तो उम्मीदवारों तुरंत भर्ती बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं.परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा. सबसे पहले उम्मीदवार को UP Police SI Admit Card 2026 का साफ प्रिंटआउट साथ रखना होगा. इसके अलावा उम्मीदवार को दो पासपोर्ट साइज फोटो और सरकार द्वारा जारी कोई वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ लेकर जाना जरूरी है. बिना पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा
परीक्षा केंद्र में किताबें, नोट्स या किसी भी प्रकार का अध्ययन सामग्री ले जाना मना है. इसके अलावा ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, टैबलेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.उम्मीदवारों को बैग, पर्स और वॉलेट भी परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं होगी.



चोट के बावजूद दिलेरी से लड़े लक्ष्य सेन

खिताब हारे पर दिल जीता

पहले वनडे में तीन प्लेयर्स करेंगे डेब्यू

बाबर को लेकर शाहीन का बयान

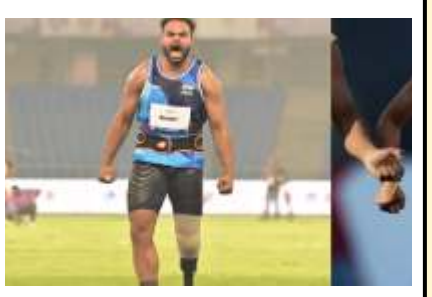
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 11 मार्च से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान के तीन प्लेयर्स को डेब्यू करने का मौका मिलेगा। इस बात की जानकारी मैच से एक दिन पहले पाक कप्तान शाहीन अफरीदी ने दी। सीरीज की शुरुआत से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक कप्तान ने बाबर आजम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बाबर को इस सीरीज से ड्रॉप नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बाबर समेत कई बड़े खिलाड़ी इस सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं हैं। 20 क्रिकेट में खराब प्रदर्शन की वजह से पिछले कुछ समय से टीम में बाबर की जगह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बाबर के बारे में पूछे जाने पर शाहीन ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए इस सीरीज के लिए किसी को ड्रॉप नहीं किया गया है। हम बस अपने युवाओं को मौके देना चाहते हैं क्योंकि वे हमारा भविष्य हैं और हम उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ मौका देना चाहते थे।



बाबर के फ्यूचर को लेकर पाक कप्तान ने आगे कहा कि जब समय आएगा, तो उन्हें अपनी भूमिका और भविष्य में क्या होने वाला है, यह पता चल जाएगा और हमें बस अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए तैयार करने की जरूरत है और यह युवाओं के लिए बाहर जाकर अपनी स्किल्स दिखाने का एक अच्छा मौका है। अब देखना ये होगा कि तीन मैचों की वनडे सीरीज में पाकिस्तान के युवा प्लेयर्स कैसा प्रदर्शन करते हैं।

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री के दूसरे सीजन का आगाज

देश की राजधानी नई दिल्ली में 11 से 13 मार्च 2026 तक वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री का दूसरा सीजन आयोजित होने जा रहा है। जिसमें भारत, रूस, नेपाल, भूटान, हांगकांग, सर्बिया, बोस्निया और मिस्र समेत आठ देशों के 250 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे।
इस बार भारत अपनी अब तक की सबसे बड़ी पैरा-एथलेटिक्स टीम उतारने जा रहा है। करीब 219 एथलीट अलग-अलग ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया के अनुसार इस आयोजन की मेजबानी मिलना विश्व पैरा खेलों में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 74 स्लॉट में बांटा जाएगा। शारीरिक अक्षमता वाले एथलीटों



के लिए 39, दृष्टिबाधित एथलीटों के लिए 29 और बौद्धिक अक्षमता वाले एथलीटों के लिए 6 कैटेगरी में स्लॉट हैं। इसके अलावा कई विदेशी दिग्गज भी कड़ी चुनौती पेश करेंगे। सर्बिया के जेल्को दिमित्रिजेविच अपनी श्रेणी (F15 क्लब थ्रो) के विश्व रिकॉर्ड धारक हैं, जिन्होंने 2012 और 2016 पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीते और सर्बिया के लिए पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता बने।

कीर्ति आजाद का बयान विवाद : ईशान और झाझरिया के बाद

हरभजन सिंह ने भी लगाई फटकार

टी20 विश्व कप जीत के बाद टीम इंडिया के मंदिर जाकर पूजा करने पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने सवाल उठाए और इसे लेकर ट्वीट किया। उनके बयान पर विवाद बढ़ गया, जिस पर ईशान किशन ने प्रतिक्रिया देने से इनकार किया, जबकि देवेंद्र झाझड़िया ने इसे खिलाड़ियों की व्यक्तिगत आस्था बताया।भारत की टी20 विश्व कप 2026 जीत के बाद जहां पूरे देश में जश्न का माहौल है, वहीं टीम इंडिया के मंदिर जाने को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद के एक ट्वीट ने इस बहस को जन्म दिया, जिस पर अब खिलाड़ियों और खेल जगत से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। न्यूजीलैंड को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 96 रनों से हराकर भारतीय टीम ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली टीम बन गया जिसने तीन टी20 विश्व कप जीते हैं। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला। विश्व कप जीतने के बाद टीम से जुड़े कई खिलाड़ी और अधिकारी धार्मिक स्थलों पर जाकर आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में आईसीसी चेयरमैन जय शाह, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव अहमदाबाद के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां पूजा-अर्चना की। तीनों ने भगवान हनुमान के चरणों में माथा टेककर देश की सफलता और टीम के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी खिलाड़ियों का स्वागत किया और टीम इंडिया के समर्थन में जयकारे लगाए।



टीम इंडिया के मंदिर जाने को लेकर कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 1983 में जब भारत ने कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप जीता था, तब टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के खिलाड़ी थे और उस जीत को भारत माता को समर्पित किया गया था।

सिर्फ 5 मिनट लेट हुई थीं जापान की मंत्री

देरी पर मंत्री ने देश से मांगी माफी

वायरल वीडियो में जापान की आर्थिक सुरक्षा मंत्री किमी ओनोडा दिखाई देती हैं. बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह वह कैबिनेट मीटिंग के लिए जा रही थीं. रास्ते में अचानक हुए सड़क हादसे की वजह से ट्रैफिक जाम लग गया और वह समय पर नहीं पहुंच पाईं.



ये तस्वीर जापान की आर्थिक सुरक्षा मंत्री किमी ओनोडा की है (Photo:Insta/onodakimijimusho)

जापान में समय की पाबंदी को बहुत गंभीरता से लिया जाता है. यहां अगर कोई थोड़ा भी देर से पहुंचे तो उसे गलत माना जाता है. इसी वजह से जापान की एक मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वजह है- मीटिंग में सिर्फ पांच मिनट की देरी, और उसके बाद पूरे देश से मांगी गई माफी. वायरल वीडियो में जापान की आर्थिक सुरक्षा मंत्री किमी ओनोडा दिखाई देती हैं. बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह वह कैबिनेट मीटिंग के लिए जा रही थीं. रास्ते में अचानक हुए सड़क हादसे की वजह से ट्रैफिक जाम लग गया और वह समय पर नहीं पहुंच पाईं. जैसे ही वह मीटिंग स्थल के पास पहुंचीं, टैक्सी से उतरते ही तेजी से दौड़ते हुए इमारत के अंदर चली गईं. हाथ में बैग लिए 43 साल के मंत्री तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए मीटिंग रूम की ओर बढ़ती दिखाई देती हैं. उनके साथ एक सहायक भी दौड़ता नजर आता है. उसी समय कैमरों ने वह पल भी रिकॉर्ड किया जब जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची मीटिंग रूम में पहुंचीं. कमरे में मौजूद सभी मंत्री खड़े होकर उनका स्वागत करते दिखाई दिए.



तेंदुलकर ने मां के लिए कार में लगवाया खास सिस्टम

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि उनके लिए परिवार सबसे पहले है. अपने बेटे की शादी में उनकी मां आराम से शामिल हो सके, इसके लिए सचिन ने खास इंतजाम किया. उन्होंने अपनी मां के लिए ऐसी विशेष कार की व्यवस्था करवाई, जिसमें उन्हें चढ़ने और उतरने में किसी तरह की परेशानी न हो. सचिन खुद भी उनका ख्याल रखते नजर आए.

मिसाइल हमलों के दौरान UAE राष्ट्रपति पहुंचे जनता के बीच

हमलों के बाद दुबई में सब ठीक!

ईरान द्वारा लगातार किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों ने दुबई की उस सुरक्षित छवि को झटका दिया है, जिसे दुनिया बरसों से मिडिल ईस्ट की सबसे सुरक्षित जगह कहती आई है.पिछले तीन दिनों में इंटरसेप्ट किए गए प्रोजेक्टाइल का मलबा शहर के कई हिस्सों पर गिरा.



कुछ फाइव स्टार होटलों में आग लगी, कई अपार्टमेंट टावरों की खिड़कियां टूट गईं और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चार कर्मचारी घायल हुए. ये सभी घटनाएं UAE सरकार और स्थानीय मीडिया द्वारा पुष्टि की गई हैं. कई प्रवासी भारतीय और विदेशी नागरिक सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं. लोगों ने आसमान में इंटरसेप्शन की चमकती लकीरें, धमाकों की आवाज़ें और धुआं उठते हुए वीडियो पोस्ट किए.दुबई जैसी शांत और सुरक्षित शहर में यह अनुभव लोगों के लिए नया और डरावना रहा,लेकिन इसी तनावपूर्ण माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को आश्वस्त कर दिया. सोमवार शाम यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिना किसी औपचारिक सिक्योरिटी शो के अचानक दुबई मॉल पहुंचे.

कुवैती एयर डिफेंस ने गलती से गिरा दिए थे अमेरिकी जेट!

महिला पायलट की मदद करता दिखा शख्स

इजरायल- अमेरिका के हमले का जवाब देते हुई ईरान अलग-अलग देशों में अमेरिकी बेस पर हमला कर रही है. हाल ही में कुवैत में अमेरिका का जेट क्रैश हो गया था. इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक कुवैती नागरिक फीमेल अमेरिकी पायलट की मदद करते देखा नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 20 सेकंड के इस वीडियो में एक फीमेल पायलट को खुले रेतीले इलाके में जमीन पर बैठा देखा जा सकता है. एक कुवैती नागरिक उसके पास जाता है . इंग्लिश में पूछता है, 'क्या आप ठीक हैं? हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद. आप सुरक्षित हैं.' कुवैती नागरिक को देखते ही पायलट जमीन से उठती नजर आती हैं. इस दौरान वो लगातार मुस्कुराती भी दिखाई दीं. दरअसल, कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के खिलाफ अभियान में शामिल तीन F-15 स्ट्राइक ईगल विमानों को गलती से मार गिराया था. ये हादसा तब हुआ जब ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों वाले खाड़ी देशों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला बोला था. उस समय आसमान में भारी सैन्य गतिविधि चल रही थी. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, इन विमानों के सभी 6 क्रू मेंबर्स सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे. हालांकि अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि किस सिस्टम से विमानों को गिराया गया, लेकिन कुवैत अमेरिका निर्मित 'पैट्रियट' मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है.

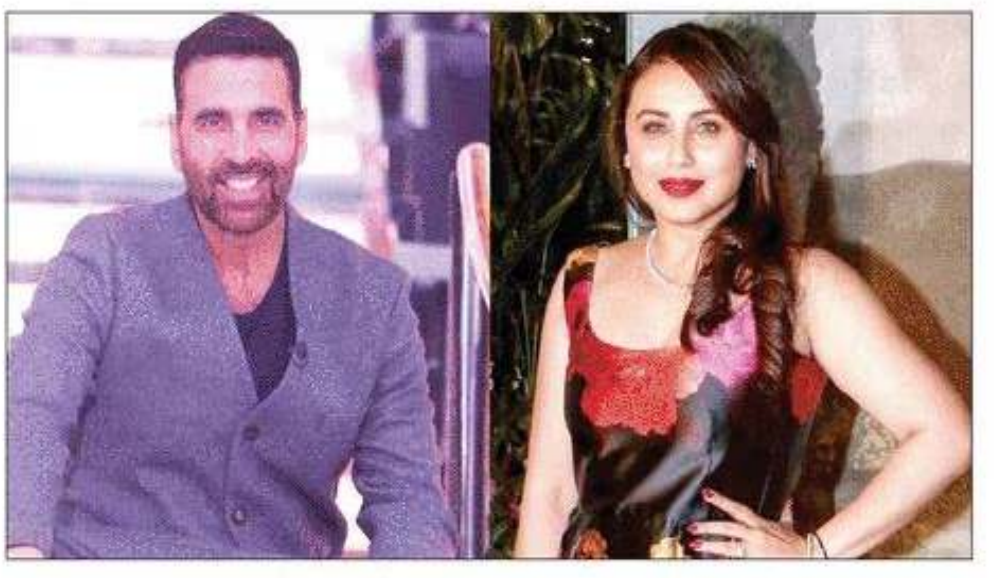


कुवैती नागरिक ने अमेरिकी पायलट को थैंक्यू कहा. (Photo: Screengrab)

क्रिएटिव डिफरेंसेज के चलते छोड़ी फिल्म?

अक्षय की 'OMG 3' में नहीं होंगी रानी

अक्षय कुमार वैसे तो कई फिल्म फ्रेंचायजी के लिए मशहूर हैं. मगर उनमें से उनकी सबसे सफल 'OMG' फ्रेंचायजी है, जो अपने सोशल टॉपिक्स को भगवान के एंगल से दिखाने के लिए पसंद की जाती है. इसके दोनों पार्ट्स अभी तक बॉक्स ऑफिस पर हिट रहे. अब 'OMG 3' को लाने की तैयारी जारी है. फिल्म 'OMG 3' से जुड़ी कुछ ही वक्त पहले एक बड़ी जानकारी सामने आई थी. कहा जा रहा था कि अक्षय की फिल्म में रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया है. इसका नाम 'Oh My Goddess' रखा जाने वाला था, जिसमें रानी को देवी के रूप में दिखाने की बात थी. फिल्म फिलहाल प्री-प्रोडक्शन स्टेज पर थी, लेकिन अब इसमें बड़ा ट्विस्ट आ चुका है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट अनुसार, रानी ने फिल्म से बाहर होने का फैसला लिया है. वजह, फिल्म के डायरेक्टर अमित राय से क्रिएटिव डिफ्रेंसेज बताई गई है. सूत्रों का कहना है, 'रानी मुखर्जी का स्क्रिप्ट को देखने का एक खास तरीका था और वो चाहती थीं कि डायरेक्टर अमित उनकी एक्सपीरियंस को फॉलो करें. लेकिन अमित के पास स्क्रिप्ट को लेकर पहले से बहुत मजबूत अलग विचार थे. दोनों एक ही पेज पर नहीं आ पाए, इसलिए रानी ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया. हालांकि मतभेद होने के बावजूद रानी को स्क्रिप्ट बहुत पसंद थी. अब मेकर्स उस रोल के लिए कोई दूसरी एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं.' हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक रानी के प्रोजेक्ट से जुड़ने या निकलने की कोई भी जानकारी कंफर्म नहीं की गई है.



शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का अभियान 11 से

गो-प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान को 26 शर्तों के साथ मिली अनुमति

लखनऊ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के 11 मार्च से प्रस्तावित तीन दिवसीय गो-प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान को प्रशासन ने 26 शर्तों के साथ अनुमति दी है। आशियाना में कार्यक्रम होगा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और नियम उल्लंघन पर अनुमति स्वतः रद्द मानी जाएगी।



टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के 11 मार्च से प्रस्तावित तीन दिवसीय 'गो-प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान' कार्यक्रम को प्रशासन ने अनुमति दे दी है। यह अनुमति 26 शर्तों के साथ दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि इन शर्तों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया गया तो अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। सोमवार देर रात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक के बाद कार्यक्रम को हरी झंडी दी गई। बैठक में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की स्मारक समिति के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम आशियाना क्षेत्र में पासी किला चौराहे के पास स्थित कांशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आशियाना, पीजीआई और कृष्णानगर थानों की पुलिस फोर्स को अलर्ट मोड पर रखा है। आयोजन स्थल पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। सूत्रों के अनुसार, आयोजकों ने तीन दिवसीय कार्यक्रम के लिए लगभग 4.50 लाख रुपये का शुल्क स्मारक समिति को जमा कराया है। आयोजकों के मुताबिक, 11 मार्च को शीतला अष्टमी के अवसर पर आशियाना स्थित कांशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल पर दोपहर 2:15 बजे से शाम 5 बजे तक मुख्य कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद 'गो-प्रविष्ठा धर्मयुद्ध' का औपचारिक शंखनाद करेंगे और उपस्थित समर्थकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में संत-समाज, विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।बताया जा रहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इन दिनों काशी से लखनऊ तक यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, मोहनलालगंज, उन्नाव और नैमिषारण्य सहित कई स्थानों पर सभाएं प्रस्तावित हैं। आयोजकों का कहना है कि यह यात्रा गौ-रक्षा को लेकर चलाए जा रहे जनजागरण अभियान का हिस्सा है और 11 मार्च को लखनऊ में इसका प्रमुख कार्यक्रम रखा गया है। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम के लिए कई महत्वपूर्ण शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इनमें स्पष्ट किया गया है कि धर्म, जाति, संप्रदाय या भाषा के खिलाफ कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा और किसी राजनीतिक या धार्मिक व्यक्ति के प्रति अमर्यादित अथवा विद्वेषपूर्ण टिप्पणी नहीं की जाएगी। नाबालिग बच्चों से विवादित नारे नहीं लगवाए जाएंगे तथा कार्यक्रम में सीमित संख्या में वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा, जिससे यातायात बाधित न हो। इसके अलावा पारंपरिक ध्वजदंड के अलावा किसी भी प्रकार की घातक वस्तु लाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजकों को अपनी मांगों का ज्ञापन सक्षम अधिकारी को सौंपना होगा और किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी आयोजकों की ही होगी। कार्यक्रम के लिए तैनात किए जाने वाले पुलिस बल का खर्च भी आयोजकों को वहन करना होगा।प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन अनिवार्य किया है और अधिकतम ध्वनि स्तर 75 डेसीबल से अधिक नहीं होने दिया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रसारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही आतिशबाजी, हथियार और हर्ष फायरिंग पर भी पूर्ण रोक लगाई गई है।

लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से कारतूस बरामद

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के बैग से कारतूस बरामद होने से हड़कंप मच गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने तुरंत यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में उसे सरोजनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया।जानकारी के अनुसार पीलीभीत निवासी दीपांकर जायसवाल इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 6ई 6521 से भुवनेश्वर जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे। यह उड़ान सुबह 9:20 बजे लखनऊ से रायपुर होते हुए भुवनेश्वर जाती है। यात्री बोर्डिंग के लिए सुरक्षा जांच से गुजर रहे थे, तभी एक्स-रे स्कैनिंग के दौरान उनके बैग में संदिग्ध वस्तु दिखाई दी।सुरक्षा कर्मियों ने जब बैग की जांच की तो उसमें 315 बोर का एक कारतूस बरामद हुआ। कारतूस मिलने के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने तुरंत यात्री को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान उससे शस्त्र लाइसेंस भी मांगा गया, लेकिन वह मौके पर कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।इसके बाद सीआईएसएफ ने यात्री को सरोजनी नगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बरामद कारतूस को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार यात्री से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कारतूस उसके बैग में कैसे आया और क्या उसके पास इसके लिए कोई वैध लाइसेंस है। फिलहाल यात्री से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जांच प्रक्रिया बेहद सख्ती से की जाती है। किसी भी संदिग्ध वस्तु मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है, ताकि हवाई यात्रा पूरी तरह सुरक्षित बनी रहे।

LPG को लेकर बढ़ी चिंता: गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें

प्रशासन बोला- 25 दिन का स्टॉक मौजूद

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब भारत के घरेलू जीवन पर भी दिखाई देने लगा है। इस संघर्ष का आज 11वां दिन है और इसी बीच देश के कई हिस्सों से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरें सामने आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर समेत राज्य के कई बड़े और छोटे शहरों से एलपीजी संकट जैसी स्थिति की सूचनाएं मिल रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद 4 से 5 दिन तक डिलीवरी नहीं हो पा रही है। इसके कारण कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। नवाबों की नगरी लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में मंगलवार को एक गैस एजेंसी पर उस समय हंगामा हो गया, जब एक ग्राहक ने आरोप लगाया कि उसकी पासबुक फाड़ दी गई। इस घटना के बाद एजेंसी के बाहर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक, हाल के दिनों में कई उपभोक्ता एक साथ दो से तीन सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी पहुंच रहे हैं, जिससे स्थिति और अधिक बिगड़ती जा रही है और वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है।हालांकि प्रशासन ने इस स्थिति को लेकर लोगों से घबराने की जरूरत नहीं बताई है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और किसी प्रकार का वास्तविक संकट नहीं है। लखनऊ के जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह के अनुसार जिले में फिलहाल लगभग 25 दिनों का एलपीजी स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में अचानक मांग बढ़ने के कारण वितरण में अस्थायी परेशानी जरूर हुई है, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इधर तेल कंपनियों ने भी गैस की कमी से जुड़ी खबरों को भ्रामक बताया है। कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को संदेश भेजकर बताया गया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घबराने



की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह भी सामने आया है कि तेल कंपनियों ने फिलहाल कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई कम कर दी है और एजेंसियों को घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले का असर होटल, रेस्तरां और ढाबा संचालकों पर पड़ रहा है। उन्हें कॉमर्शियल सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनके व्यवसाय पर असर पड़ रहा है और कई कारोबारियों को संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 4.26 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं, जिनमें से करीब 1.87 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। राज्य में प्रतिदिन औसतन 5 से 6 लाख गैस सिलेंडरों की खपत होती है।इसी बीच प्रशासन ने गैस बुकिंग की प्रक्रिया को भी अधिक सख्त कर दिया है। अब करीब 80 प्रतिशत बुकिंग ओटीपी के माध्यम से की जाएगी। जिन उपभोक्ताओं को ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने और मोबाइल नंबर अपडेट कराने की सलाह दी गई है।

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास योजना लागू

टीवी भारतवर्ष लखनऊ



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में शहरी क्षेत्रों के लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मिनी मध्यम आय वर्ग (मिनी एमआईजी) के लिए किफायती मकानों का निर्माण किया जाएगा।सरकार के अनुसार इन मकानों की कीमत अपेक्षाकृत कम रखी जाएगी और इनका आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मकान बनाए जाएंगे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब नौ लाख रुपये होगी। इससे बड़े मकानों की कीमत रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की अनुमति से तय की जाएगी।योजना के तहत इन मकानों का निर्माण विकास प्राधिकरणों के साथ निजी बिल्डरों के सहयोग से कराया जाएगा। बिल्डरों को बड़े मकानों के साथ छोटे और किफायती मकान बनाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें भू-उपयोग परिवर्तन और फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में भी छूट प्रदान की जाएगी, ताकि अधिक संख्या में किफायती आवास विकसित किए जा सकें।सरकार ने मकान खरीदने वाले लाभार्थियों को भी राहत देने का निर्णय लिया है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ढाई लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना आसान हो सकेगा।कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत किफायती आवास (एएचपी) और किफायती किराया आवास (एआरएच) घटकों के क्रियान्वयन के लिए नई नीति जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

मौलाना का पुतला जला रहे थे खुद ही जल गए

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी का पुतला फूंकते समय आज बड़ा हादसा हो गया। आग से करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश और प्रदेश उपाध्यक्ष विकास सिंह झुलस गए। दोनों को सिविल अस्पताल ले जाया गया। उन्हें बचाने के चक्कर में कई कार्यकर्ता भी मामूली रूप से झुलस गए। पुलिसकर्मियों ने अग्निशमन संयंत्र से आग पर काबू पाया। मौलाना अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिया है। इसके बाद से प्रदेशभर में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है। करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज शाम हजरतगंज में मौलाना अब्दुल्ला का पुतला फूंकने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने पहले पुतले को जूते से पीटा। उसके बाद पुतले पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग की ऊंचीं लपटें निकलीं। प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हाथ और पैर झुलस गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

आयुष्मान योजना में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा

लखनऊ के कई निजी अस्पतालों में मिली गंभीर अनियमितताएं

आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज और क्लेम के नाम पर फर्जीवाड़े के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट और स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में राजधानी लखनऊ के कई निजी अस्पतालों में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। जांच के दौरान कई अस्पतालों में मरीजों की संख्या, सुविधाओं और स्टाफ को लेकर किए गए दावों और वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर पाया गया।जांच में सामने आया कि लखनऊ स्थित शान्या स्कैन हॉस्पिटल ने आयुष्मान योजना के तहत 592 मरीजों को भर्ती दिखाते हुए दावा किया था, जबकि निरीक्षण के दौरान वहां केवल 40 मरीज ही भर्ती पाए गए। अस्पताल प्रबंधन इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके अलावा अस्पताल में बेड के बीच की दूरी भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई और कई अन्य कमियां भी सामने आईं।अधिकारियों के अनुसार अस्पताल ने योजना के तहत मरीजों को पेट स्कैन और कीमोथेरेपी के लिए भर्ती दिखाया था, जबकि वास्तविकता में केवल पेट स्कैन ही किया गया था। अस्पताल में कुल 28 बेड ही उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद उससे कहीं अधिक मरीजों को भर्ती दर्शाया गया। इस मामले में अस्पताल को विस्तृत नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसी तरह अद्भुत हॉस्पिटल के निरीक्षण में भी कई गंभीर खामियां सामने आईं। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में संक्रमण नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। नियमानुसार तीन ड्यूटी डॉक्टर होने चाहिए थे, लेकिन निरीक्षण के समय वहां कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं मिला।ओम साई हॉस्पिटल ने आयुष्मान योजना के तहत 10 बेड दर्शाकर पंजीकरण कराया था, जबकि मौके पर केवल पांच बेड ही पाए गए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कोई पूर्णकालिक ड्यूटी डॉक्टर और ओटी टेक्नीशियन भी मौजूद नहीं थे।अर्जुनगंज स्थित पुष्पांजली हॉस्पिटल में भी जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। पोर्टल पर नौ मरीज दर्ज थे, लेकिन मौके पर केवल एक ही आयुष्मान लाभार्थी मौजूद मिला। अस्पताल में कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं पाया गया और दवाइयों के रखरखाव की व्यवस्था भी अव्यवस्थित मिली।वहीं शताब्दी हॉस्पिटल का संचालन भूमिगत बेसमेंट में किया जा रहा था। अस्पताल में आयुष्मान योजना से संबंधित हेल्प डेस्क



नहीं था और योजना के टीएमएस पोर्टल के संचालन के लिए कोई प्रशिक्षित स्टाफ भी उपलब्ध नहीं था। अर्जुनगंज स्थित मेडी हेल्थ हॉस्पिटल में निरीक्षण के दौरान केवल एक एमबीबीएस डॉक्टर ही ड्यूटी पर पाए गए। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट से संबंधित प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त हो चुकी थी और फायर एनओसी भी जारी नहीं की गई थी।

उन्नाव पुलिस की बड़ी उपलब्धि

जन शिकायतों के निस्तारण में उन्नाव पुलिस अव्वल

टीवी भारतवर्ष उन्नाव



उन्नाव पुलिस ने फरवरी माह की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) रैंकिंग में पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि पुलिस की कार्यकुशलता, शिकायतों के प्रभावी निस्तारण तथा जनसुनवाई के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस सफलता से न केवल जिले की पुलिस का मनोबल बढ़ा है, बल्कि प्रदेश स्तर पर भी उन्नाव की कार्यप्रणाली की सराहना की जा रही है।फरवरी माह की आईजीआरएस रैंकिंग में उन्नाव जिले के सभी 21 पुलिस थानों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि पुलिस टीम के समर्पण, सतत निगरानी और जिम्मेदार कार्यशैली का परिणाम मानी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके कारण जिले की समग्र रैंकिंग प्रदेश में सबसे बेहतर रही।पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह के नेतृत्व में उन्नाव पुलिस ने जन शिकायतों के समाधान में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया गया। साथ ही, प्रत्येक मामले में पारदर्शी जांच प्रक्रिया अपनाई गई ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।उन्होंने कहा, "जनसुनवाई और न्याय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता का भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।" पुलिस विभाग लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक नागरिक की शिकायत को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ सुना जाए और उसका उचित समाधान किया जाए।पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा की व्यवस्था की गई। प्रत्येक थाने में साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें लंबित मामलों की स्थिति और उनकी प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। इन बैठकों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए, ताकि शिकायतों के समाधान में किसी प्रकार की देरी न हो।इसके अलावा, शिकायतकर्ताओं से भी समय-समय पर प्रतिक्रिया ली गई, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी समस्याओं का समाधान संतोषजनक तरीके से हुआ है या नहीं। इस प्रक्रिया ने शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।पुलिस विभाग में इस उपलब्धि को लेकर उत्साह का माहौल है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि यह सफलता पूरी टीम के सामूहिक प्रयास और जनता के सहयोग का परिणाम है। अधिकारियों के अनुसार, आईजीआरएस में बेहतर प्रदर्शन से पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ती है और आम जनता का विश्वास भी मजबूत होता है।प्रशासन ने उन्नाव पुलिस की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए पूरी टीम को बधाई दी है। अधिकारियों का कहना है कि अन्य जिलों को भी इस कार्यप्रणाली से प्रेरणा लेकर शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए।आईजीआरएस रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करना उन्नाव पुलिस के लिए गर्व की बात है। यह उपलब्धि भविष्य में पुलिस को और अधिक जिम्मेदारी तथा प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, ताकि जनता को त्वरित और न्यायपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

उन्नाव में महिला का शव फांसी पर लटका मिला



टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला है। यह घटना कोतवाली क्षेत्र के इंद्रा नगर मोहल्ले में हुई, जहां महिला अपने भाई के घर आई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। मृतका की पहचान 50 वर्षीय राम रति पत्नी राजेश, निवासी ग्राम जगदीशपुर, थाना अजगैन के रूप में हुई है। वह सोमवार शाम करीब 4 बजे अपने भाई राम दास के इंद्रा नगर स्थित घर आई थीं। परिजनों के अनुसार, वह सामान्य दिख रही थीं और उन्होंने किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। घटना के समय राम रति घर में अकेली थीं। उनके भाई राम दास और भाभी दवा लेने के लिए बाहर गए हुए थे। जब वे वापस लौटे, तो उन्होंने राम रति का शव कमरे में लगे पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ पाया। परिजनों ने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। मृतका के दो बेटे हैं, जिनमें 30 वर्षीय राम लखन और 20 वर्षीय सुगवीर शामिल हैं। मां की आकस्मिक मौत की खबर सुनकर दोनों बेटे भी मौके पर पहुंचे। परिवारजनों का दुख देखकर वहां का माहौल गमगीन हो गया। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा।



उन्नाव में दबंगों का हमला, पति-पत्नी घायल; पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मारपीट का एक मामला सामने आया है, जिसमें दबंग प्रवृत्ति के लोगों पर घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगा है। घटना गदनखेड़ा बाईपास क्षेत्र की बताई जा रही है। पीड़ित दीपू तिवारी के अनुसार मोहल्ले के ही रहने वाले राजू द्विवेदी और उनके पुत्र ओम द्विवेदी दो-तीन अन्य लोगों के साथ उनके घर पहुंच गए और अचानक मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान घर में मौजूद महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोटें आईं। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने मारपीट के साथ-साथ घर के बाहर खड़ी गाड़ी को भी तोड़ दिया।घटना के बाद घायल परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित दीपू तिवारी का आरोप है कि हमलावर दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं और मोहल्ले में आए दिन लोगों के साथ मारपीट करते रहते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपित उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देते हैं।मामले की जानकारी मिलने पर उन्नाव के पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने कहा कि घटना की जांच कराई जा रही है और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया है।



डीएम की समीक्षा बैठक में खुली योजनाओं की पोल, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत ब्लॉक मिशन प्रबंधकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप संतोषजनक प्रगति न मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कई ब्लॉक मिशन प्रबंधकों को फटकार लगाई।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विकासखंडवार समूह गठन, परिवार संतृप्तिकरण, रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड तथा कैश क्रेडिट लिमिट की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। समीक्षा के दौरान असोहा, पुरवा, हिलौली, सरोसी और बांगरमऊ विकासखंडों में कार्य की प्रगति बेहद खराब पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित ब्लॉक मिशन प्रबंधकों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि लापरवाही बरतने वाले ब्लॉक मिशन प्रबंधकों की दो दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाए, ताकि उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कई स्थानों पर वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप स्वयं सहायता समूहों का गठन नहीं किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने गठित स्वयं सहायता समूहों की वास्तविक स्थिति की जांच कराने के लिए मजिस्ट्रेटियल जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि समूह केवल कागजों पर ही न बने हों, बल्कि वास्तव में सक्रिय होकर कार्य भी कर रहे हों। जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की बैठक आयोजित करें और उन्हें दी गई धनराशि की जांच करें। साथ ही, समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों का सत्यापन करें तथा संबंधित अभिलेखों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।बैठक के दौरान लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में सुधार न होने पर जिलाधिकारी ने जिला समन्वयक मनरेगा पर भी नाराजगी व्यक्त की और कार्यप्रणाली में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाना है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी विकासखंड में फर्जी स्वयं सहायता समूहों का गठन न किया जाए और केवल वास्तविक तथा सक्रिय समूह ही बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि जनपद में महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन में राज्य के औसत से कम प्रगति किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

ट्रैक्टर-बाइक की टक्कर में चालक की मौत

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में अतहा-पावा मार्ग पर मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे बाइक के अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकराने के बाद पलट जाने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और इलाके में शोक का माहौल छा गया।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान अतहा गांव निवासी महेश (18) पुत्र राजू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महेश अपनी बाइक से अतहा-पावा मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सड़क किनारे एक ट्रैक्टर खड़ा था। आशंका जताई जा रही है कि युवक या तो ट्रैक्टर से टकरा गया या उसे बचाने की कोशिश में बाइक का संतुलन खो बैठा, जिससे बाइक पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सड़क पर खून बिखरा देख आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही सफीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसा किस परिस्थिति में हुआ।

मौरावां-उन्नाव मार्ग पर निजी बस पलटी, चीख-पुकार के बीच सुरक्षित निकाले गए यात्री

उन्नाव जिले में मंगलवार दोपहर एक निजी बस के पलटने से अफरा-तफरी मच गई। मौरावां से सवारी लेकर उन्नाव जा रही बस दही-मोहनलालगंज मार्ग पर बैगांव मोड़ के पास अचानक पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। बस पलटते ही अंदर बैठी सवारियों में चीख-पुकार मच गई।घटना की आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान तुरंत मौके पर पहुंचे और बस में फंसी सवारियों को बाहर निकालने में मदद की। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद बस का चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इसके साथ ही पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस की ओर से उपनिरीक्षक सियाराम चौरसिया और विनोद सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस अचानक सड़क पर दाईं ओर चलती चली गई और फिर अनियंत्रित होकर पलट गई। उस समय सामने से कोई वाहन भी नहीं आ रहा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बस की ब्रेक या स्टेयरिंग फेल हो जाने के कारण चालक ने बस को सड़क किनारे खंती में पेड़ के पास पलटाकर बड़ा हादसा टालने की कोशिश की होगी।बस में पुरवा स्थित बीएएसएस इंटर कॉलेज की बोर्ड परीक्षा की कॉपियां भी रखी थीं। स्कूल कर्मचारी विजय उर्फ गुड्डू इन कॉपियों को लेकर उन्नाव के स्ट्रांग रूम में जमा करने जा रहे थे। हादसे के बाद इन कॉपियों को सुरक्षित निकालकर एक निजी वाहन के माध्यम से गंतव्य स्थान के लिए भेज दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर निजी बसों के पलटने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद वाहनों की फिटनेस और ओवरलोडिंग को लेकर प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती।

यूपी में गर्मी ने दिखाए तेवर, पहली बार 38°C के पार पहुंचा पारा

कई शहरों में धुंध, बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ने लगा है और इस सीजन में पहली बार तापमान 38°C के पार पहुंच गया। कई शहरों में सुबह धुंध छाई रही। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी जल्दी शुरू होने और हीटवेव का खतरा बढ़ने की आशंका है।



टीवी भारतवर्ष यूपी

उत्तर प्रदेश में गर्मी ने धीरे-धीरे अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस सीजन में पहली बार प्रदेश का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं मंगलवार सुबह लखनऊ, कानपुर समेत प्रदेश के करीब 10 शहरों में धुंध छाई रही, जिससे कई जगह विजिबिलिटी घटकर 400 से 500 मीटर तक सिमट गई। पिछले 24 घंटे में बुंदेलखंड का बांदा जिला प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा झांसी, आगरा, उरई और हमीरपुर जैसे शहरों में भी तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का एहसास हुआ। शाम के समय कई इलाकों में 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलीं, जिससे कुछ हद तक राहत मिली।लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि बढ़ते तापमान और हवा में नमी की वजह से सुबह के समय कोहरे और दिन में धुंध जैसे हालात बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही 15 मार्च से प्रदेश के मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कई शहरों में मौसम का अलग-अलग असर देखने को मिला। राजधानी लखनऊ में सुबह-सुबह धुंध छाई रही और विजिबिलिटी कम रही। यहां अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, हालांकि तेज हवाओं के कारण लोगों को कुछ राहत महसूस हुई। कानपुर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। बिल्हौर क्षेत्र में विजिबिलिटी मात्र 30 मीटर तक सिमट गई। दिन में मौसम साफ रहने और तापमान बढ़ने का अनुमान है। यहां अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।वाराणसी में सुबह से हल्की धुंध छाई रही और आसमान में हल्के बादल दिखाई दिए। यहां तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा विजिबिलिटी लगभग 500 मीटर रही। प्रयागराज में भी आसमान में धुंध और बादल छाए रहे, जबकि हल्की धूप भी निकली। यहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री रहने का अनुमान है। गोरखपुर में सुबह से ही हल्की धुंध और बादल छाए रहे। यहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। गाजियाबाद में सुबह के समय बादल छाए रहे और बीच-बीच में हल्की धूप खिलती रही। यहां दिन में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। बरेली में मौसम ठंडा बना हुआ है और बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। वहीं जालौन में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई।मौसम विभाग के अनुसार 11 मार्च को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। 12 मार्च को भी कई जगह बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 13 मार्च को मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार इस साल कई इलाकों में लंबे समय तक हीटवेव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जब मैदानों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है या सामान्य से 4 से 6 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जाता है, तो उसे हीटवेव माना जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है और लू लगने का खतरा भी बढ़ जाता है।

पति ने दो बच्चों की हत्या कर की खुदकुशी

टीवी भारतवर्ष यूपी

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के नौतनवा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एसएसबी की सफाईकर्मी की पत्नी के पति, अमरीश ठाकुर, ने अपने दो मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। घटना के बाद मामले में नया मोड़ तब आया जब पुलिस को मृतक के द्वारा बनाई गई दो वीडियो और सुसाइड नोट मिले। इन वीडियो और नोट में अमरीश ने अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया।अमरीश ने खुदकुशी से पहले दीवार पर सुसाइड नोट लिखा और दो वीडियो बनाए, जिनमें उसने अपने दर्द और परेशानियों का खुलासा किया। वीडियो में उसने साफ तौर पर कहा कि उसकी मौत के बाद उसके शव को उसकी पत्नी न छुए और शव को उसके घरवालों को सौंप दिया जाए।मामले में मृतक के मामा अवधेश कुमार ने बताया कि वीडियो में अमरीश ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी बंदना, ससुर रामअवतार, सास चंदा देवी, साला नवीन कुमार, भाभी सुनीता देवी और अमरनाथ भारती मिलकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उसने कहा कि इन लोगों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी।स्थानीय पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और वीडियो व सुसाइड नोट को सबूत के तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि अमरीश और उसके परिवार को किस प्रकार की मानसिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

पकौड़ी लेने गया पति

बस में बैठी पत्नी गायब

टीवी भारतवर्ष अमरोहा



उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अमरोहा (Amroha) जिले के देहात थाना क्षेत्र के एक युवक की चार माह पहले हुई शादी में ही अजीब घटना सामने आई। रामपुर (Rampur) जिले के सैफनी थाना क्षेत्र की युवती होली मनाने के लिए अपने मायके आई थी। सोमवार सुबह उसका पति उसे लेने सैफनी पहुंचा और दोनों पहले बस से बिलारी आए, फिर दोपहर में बिलारी बस स्टैंड से मुरादाबाद जाने के लिए रोडवेज की बस में बैठे। जानकारी के अनुसार विवाहिता ने अपने पति को बस स्टैंड के पास कैंटीन भेजा और कहा कि पकौड़ी और पानी की बोतल लेकर आए और पकौड़ी अपने सामने गर्म करवाकर तेज सिकवा कर लाएं। लेकिन जब पति पकौड़ी लेकर बस में वापस आया, तो उसकी पत्नी सीट पर नहीं थी। उसने फोन किया, लेकिन विवाहिता का मोबाइल स्विच ऑफ था। बस में मौजूद यात्रियों ने बताया कि महिला किसी से मोबाइल पर बात करते हुए बस से नीचे उतर गई थी। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि विवाहिता का शादी से पहले ही अपने गांव के एक युवक के साथ प्रेम संबंध था। पति ने अपनी पत्नी को काफी देर तक आसपास तलाशा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बाद में उसने अपने घर और ससुराल में भी इस घटना की सूचना दी। थाना बिलारी पुलिस ने कहा कि फिलहाल उनके पास इस घटना की कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। स्थानीय लोग यह आशंका जता रहे हैं कि विवाहिता अपने पति को धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ चली गई है।

कानपुर में गंगा मेला: रंगों में सराबोर शहर

सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने लोगों संग किया डांस

टीवी भारतवर्ष कानपुर



कानपुर में एक मंदिर के पुजारी की नॉनवेज खाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस पर लोग भड़क गए। रविवार रात करीब 50-60 लोग मंदिर पहुंचे और पुजारी को मंदिर परिसर से बाहर बुलाने लगे। जब पुजारी बाहर आने में आनाकानी करने लगे तो कुछ लोग मंदिर के अंदर घुस गए और उन्हें घसीटते हुए बाहर ले आए। इसके बाद वायरल तस्वीर को लेकर उनसे सवाल-जवाब करने लगे। इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। गुस्साई भीड़ ने पुजारी पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। पुजारी खुद को बचाने के लिए भागने लगा तो लोगों ने उसे दौड़ाकर पीटा। मंदिर के आसपास की दुकानों में काम करने वाली महिलाएं बीच-बचाव के लिए आगे आईं। वे पुजारी को छोड़ देने की मिन्नतें करती रहीं, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों ने कहा, पुजारी धर्म भ्रष्ट कर रहा है। करीब एक घंटे तक मौके पर हंगामा चलता रहा। यह घटना रावतपुर के केशवपुरम स्थित भूतेश्वर मंदिर की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह पुजारी को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई।

